महाराष्ट्र राज्य

बनाम

मारवांजी एफ.देसाई और अन्य

14 दिसम्बर 2001

(डी.पी. महापात्र और उमेश सी. बनर्जी जे.जे.)

बॉम्बे सरकारी परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1955 - धारा 4, 5, 6 और 7 -सार्वजनिक परिसर - निजी कब्जाधारियों को पट्टे पर देना - सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जाधारियों को बेदखली नोटिस जारी करना - बाद में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा "कार्यवाही को छोड़ना" - अधिनियम की धारा 7 के तहत राज्य सरकार द्वारा अपील - अपील को बनाये रखने के संबंध में कब्जाधारियों द्वारा प्रारंभिक आपत्ति - निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई - अपील पर, उच्च न्यायालय ने माना कि राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, जो सरकार की विस्तारित शाखा या विभाग है - वैधता – माना की अधिनियम की धारा 7 स्पष्ट रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित " प्रत्येक आदेश" के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है - सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अर्ध न्यायिक प्रकृति की है - "कार्यवाही ख़ारिज कर दी गई', इसकी तुलना कार्यवाही ख़ारिज करने के आदेश से नहीं की जा सकती - उच्च न्यायालय का आदेश रद्द क़ानून की व्याख्या

अभिव्यक्ति "प्रत्येक आदेश"- की व्याख्या - माना, यदि प्रतिबंधात्मक अर्थ शब्द "प्रत्येक" के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है तो कुल अतिरेक होगा जिससे विधायिका बचती है - उद्देश्यों और कारणों का कथन निस्संदेह निर्माण के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका और सहायता है, - लेकिन विधायी आशय को पूरे क़ानून को पढ़कर इकट्ठा करना पड़ता है - जहाँ क़ानून की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है, वहाँ व्याख्या के लिए कोई बाहरी सहायता की अनुमति नहीं है- जहाँ क़ानून की भाषा स्पष्ट और श्रेणीबद्ध है, वहाँ व्याख्या के लिए किसी बाहरी सहायता की अनुमति नहीं है।

शब्द और वाक्यांशः

अभिव्यक्ति "प्रत्येक आदेश" - बॉम्बे सरकारी परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1955 की धारा 7 के संदर्भ में अर्थ राज्य सरकार से संबंधित भूमि के कुछ भूखंड प्रतिवादी-कब्जाधारियों को पट्टे पर दिए गए थे। चूंकि सरकार उक्त भूखंडों को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए चाहती थी, इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने बॉम्बे सरकारी परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1955 की धारा 4(2) के तहत प्रतिवादी-कब्जाधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। हालाँकि, बाद में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने बेदखली की कार्यवाही को रद्द करने का आदेश पारित किया। व्यथित होकर, राज्य सरकार ने सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष अधिनियम की धारा 7 के तहत अपील दायर की। उत्तरदाताओं ने अपील की

विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई। आपत्ति खारिज कर दी गई। इसके बाद, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसे यह कहते हुए अनुमति दे दी गई कि राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 7 के तहत सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है, जो सरकार का एक विस्तारित हाथ या विभाग है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान अपील।

अपीलकर्ता - राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 7 को सही ढंग से पढ़ने पर यह नहीं माना जा सकता है कि सक्षम प्राधिकारी सरकार का एक विस्तारित अंग या एक विभाग था और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसे सरकार कहा जा सकता है। और इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में गलती की कि राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं था; अधिनियम की धारा 7 में "प्रत्येक आदेश" शब्द का उपयोग इंगित करता है कि यह धारा 4 या 5 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को व्यापक रूप से कवर करता है; आदेश और कार्यवाही छोड़ने के बीच अंतर करने का प्रयास पूरी तरह से कृत्रिम और अतार्किक था।

अपीलों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. उच्च न्यायालय का यह आदेश कि राज्य सरकार के पास सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ बॉम्बे सरकारी परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत अपील करने की कोई शक्ति नहीं है, बरकरार नहीं रखा जा सकता है। (661-सी]

2.1. अधिनियम की धारा 7 में शब्द "आदेश" से ठीक पहले आने वाला शब्द "प्रत्येक" बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि सरकार के खिलाफ कोई आदेश होने की स्थिति में अपील का अवसर प्रदान किया जा सके। विधायिका ने जानबूझकर "प्रत्येक आदेश" का उपयोग किया है और यदि प्रतिबंधात्मक अर्थ को जिम्मेदार ठहराया गया है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, तो "प्रत्येक" शब्द किसी भी स्थिति में पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है लेकिन चूंकि विधायिका सरकार बनाम मारवांजी पी.देसाई 649 अतिरेक से बचती है और विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक शब्द प्रावधान को एक अर्थ देना होगा और 'प्रत्येक शब्द के किसी भी अर्थ का श्रेय अपने आप में व्याख्या को अस्वीकार कर देगा जैसा कि उच्च न्यायालय के पक्ष में पाया गया है। "प्रत्येक आदेश" शब्दों का उपयोग इंगित करता है कि इसमें धारा 4 या धारा एस के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। यह विचार कि सक्षम प्राधिकारी सरकार का एक अंग या विंग है और इस तरह उसे अपने आदेश के खिलाफ विरोध दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह क़ानून की पूरी तरह से गलत व्याख्या है और

यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक ख़तरनाक प्रस्ताव को जन्म देगा। जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। [659-ई; 661-बी; 658-जी; 659-सी]

2.2. क़ानून पर पूरी तरह से विचार करना होगा और एक विशेष प्रावधान से एक शब्द चुनना और इस तरह वस्तुओं और कारणों के बयान के विपरीत इसका विश्लेषण करना न तो स्वीकार्य है और न ही उचित है। क़ानूनों के निर्माण और व्याख्या के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं। और सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के प्रशासनिक होने के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष न केवल क़ानून का उल्लंघन है, बल्कि निर्माण के सभी मानदंडों और सिद्धांतों के विपरीत है। विधायिका के सच्चे इरादे को इकट्ठा करना होगा और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा का उचित ध्यान रखते हुए उसकी उचित भावना को समझना होगा। वस्तुओं और कारणों का विवरण निस्संदेह निर्माण में सहायक और एक प्रभावशाली मार्गदर्शक है, लेकिन व्याख्याओं और इरादे को क़ानून की संपूर्णता से एकत्र करना होगा और जब किसी मंच पर अपील प्रदान करने वाले अनुभागों की भाषा स्पष्ट और श्रेणीबद्ध हो तो उसकी व्याख्या में कोई बाहरी सहायता की अनुमति नहीं है। [660-एफ; एच; 661-ए)

3. "कार्यवाही छोड़ दी गई" की तुलना किसी कार्यवाही को ख़ारिज करने के आदेश के साथ नहीं की जा सकती। सक्षम प्राधिकारी ने नोटिस

जारी किए और पक्षों को सुनवाई का अवसर देने पर, "कार्यवाही बंद" दर्ज करके कार्यवाही समाप्त कर दी। प्रतिवादियों के खिलाफ अधिनियम की धारा 4 के तहत शुरू की गई कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के फैसले से समाप्त हो जाती है और इस प्रकार सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा कार्यवाही के निर्धारण के तथ्य को न समझकर उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से त्रुटि में पड़ गया। [660-सी; 658-जी; एच; 659-ए).

4. अधिनियम की धारा 6(ए) स्पष्ट रूप से इस उद्देश्य के लिए प्रावधान करती है कि अधिनियम के तहत जांच करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के पास वही शक्तियां होंगी जो किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट में निहित होती हैं। हालांकि यह सच है कि यह अधिकार गवाहों को बुलाने और किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को 650 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2001 एसयूपीपी. 5 एससीआर] लागू करने और शपथ पर उसकी जांच करने या दस्तावेजों की खोज और पेशी की आवश्यकता तक सीमित है, लेकिन यह कार्यवाही की अर्ध न्यायिक प्रकृति को खत्म नहीं करता है और एक मामले के रूप में वास्तव में यह ऐसे निष्कर्ष को विश्वसनीयता प्रदान करता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति को लागू करना केवल न्यायालय के आदेश द्वारा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, यह विशिष्ट शक्ति है जो सक्षम प्राधिकारी को प्रदान की जाती है ताकि सक्षम प्राधिकारी को प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने पर कानून के अनुसार

आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। विचाराधीन मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स दर्शाता है कि वास्तव में कलेक्टर की ओर से एक अनुरोध पत्र था और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान कलेक्टर का प्रतिनिधित्व प्रावधानों के संदर्भ में नोटिस के साथ एक अधिकारी द्वारा भी किया गया था। और इस कारण से कार्यवाही को अर्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है। [695-एच; 660-ए-सी; 659-जी]

यूपी आवास एवं विकास परिषद एलआरएस द्वारा एवं अन्य बनाम ज्ञान देवी, [1995] 2 एससीसी पृष्ठ 326 और नॉर्दर्न प्लास्टिक्स लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स एमएफजी. कंपनी लिमिटेड और अन्य, [1997] 4 एससीसी 452, प्रतिष्ठित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7677 / 1994

बॉम्बे उच्च न्यायालय डब्ल्यू.पी. नंबर 1077/1985 के निर्णय और आदेश दिनांक 29.1.88 से।

साथ में

सीए संख्या 7678, 7679, 7680, 7681, 7682 / 1994

एस.के. ढोलकिया, एस. गणेश, एस.वी. देशपांडे, पी.एस. सुधीर, के.जे. जॉन के लिए, अमित ढींगरा, डी.पी. मोहंती, एस.ए. पूनावाला, पी.एच. पारेख के लिए उपस्थित पक्षों के लिए

न्यायालय का निर्णय बनर्जी, जे. द्वारा सुनाया गया।

वर्तमान में इस अदालत के समक्ष मामला बॉम्बे सरकारी परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1955 की धारा 7 के कार्यक्षेत्र का दायरा और इसकी प्रयोज्यता से संबंधित है, अर्थात, अधिनियम 1955 की धारा 4 के तहत जारी नोटिस के संदर्भ में 'कार्यवाही छोड़ने' का आदेश और परिणामी सरकारी परिसर से बेदखली के लिए शुरू की गई कार्यवाही को खारिज करने से। हालाँकि, सरकार बनाम मारवांजी पी.देसाई 651 उच्च न्यायालय ने इसका उत्तर नकारात्मक और कब्जाधारियों के पक्ष में दिया। इसलिए विशेष अनुमति दिए जाने पर इस न्यायालय के समक्ष अपील की जाती है।

तथ्यात्मक अंक को ध्यान में रखते हुए मोटे तौर पर यह प्रतीत होता है कि बायकुला प्रभाग, बॉम्बे में राज्य सरकार से संबंधित भूमि के विभिन्न भूखंड कई कब्जेदारों को पट्टे पर दिए गए थे और 1968 से उनके कब्जे में थे। चूंकि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूखंड चाहती थी, इसलिए सक्षम प्राधिकरण ने 26 नवंबर, 1979 को अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत रहने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और हालांकि, 16 दिसंबर, 1980 के एक आदेश द्वारा कार्यवाही को रद्द कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 7 के तहत सिटी सिविल कोर्ट, बॉम्बे के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष अपील की गई, जिसमें अपील को बनाये रखने के संबंध में कब्जाधारियों द्वारा प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी। हालाँकि, आपत्ति को विद्वान न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था और उसके बाद प्रतिवादियों ने संविधान के

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दर्ज करने पर रिट याचिका की अनुमति दी: "न तो अधिनियम की धारा 7 के तहत और न ही अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत, सक्षम प्राधिकारी के किसी भी निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया है।"

संयोग से, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क़ानून की किताब में कानून (बॉम्बे सार्वजनिक परिसर अधिनियम) की शुरूआत पूरी तरह से सरकार को दीवानी अदालतों में दीवानी मुकदमों के माध्यम से किसी भी लंबी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिए बिना अपनी संपत्ति से अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। कानून के संदर्भ में प्रदान की गई मशीनरी को एक अर्ध कानूनी/न्यायिक प्राधिकरण नहीं कहा जा सकता है जैसा कि हम जल्द ही देखेंगे, लेकिन ऐसा करने से पहले, आइए उससे संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर एक नज़र डालें:

> ["..... इसलिए, ये प्रावधान दर्शाते हैं कि बेदखल करने या किराया या हर्जाना वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू करने, विवाद का फैसला करने के साथ-साथ इसे लागू करने की शक्तियां एक ही प्राधिकरण में निहित हैं। इसलिए यह सरकार की एक विस्तारित शाखा या विभाग से अधिक कुछ

नहीं है और सभी उद्देश्यों के लिए सरकार ही है। जब ऐसा है, तो राज्य सरकार के लिए सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील के अधिकार का दावा करना अपने स्वयं के निर्णय के विरुद्ध उक्त अधिकार का दावा करना है जो की संभवतः असमर्थनीय है।"

हालाँकि, इस समय, धारा 4, 5, 6 और 7 में निहित प्रावधानों के प्रासंगिक निचोड़ के साथ-साथ अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर इसकी उचित सराहना के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए।

'उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों को बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चॉल्स, बॉम्बे जैसे सरकारी परिसरों में आवास आवंटित किया है। इन परिसरों पर लंबे समय से कब्जा है और यह देखा गया है कि किराए का संग्रह पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। इसी तरह, वहाँ अनधिकृत कब्जे और उप-किरायेदारी के मामले हैं। सरकार के लिए परिसर के खाली कब्जे को पुनर्प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है जब किराए का भारी बकाया होता है या अनधिकृत कब्जे के मामले में या जब आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होता है। अनाधिकृत कब्जेदारों के खिलाफ और बकाया किराए की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना एक लंबी प्रक्रिया है जिसके

परिणामस्वरूप राजस्व की हानि होती है। इसलिए, सरकार को सरकारी कर्मचारियों के उपयोग और कब्जे के लिए आवंटित परिसर के कब्जे को नियंत्रित और विनियमित करने में सक्षम बनाना है और अन्य और उससे जुड़े कुछ अन्य मामलों के लिए, अनधिकृत कब्जे, उप-किराए पर देने और किराए के बकाया के मामलों से निपटने के लिए सरकार को प्रभावी शक्तियों से लैस करना आवश्यक माना जाता है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य इन सभी मामलों के लिए उपाय प्रदान करना है।"

"धारा 4: बेदखल करने की शक्ति- (1) यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है -

(ए) कि किसी भी सरकारी परिसर पर कब्जा करने के लिए अधिकृत व्यक्ति, चाहे इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में हो-

(i) दो महीने से अधिक की अवधि के लिए ऐसे परिसर के संबंध में कानूनी रूप से देय किराए का भुगतान नहीं किया गया है, या

(ii) राज्य सरकार, या सक्षम प्राधिकारी, या उस अधिकारी की अनुमति के बिना, जिसके पास राज्य सरकार या किसी अन्य की ओर से परिसर है या जिसके नाम पर लिया गया है, ऐसे पूरे परिसर या उसके किसी हिस्से को उप-किराए पर दे दिया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी, या सरकार बनाम मारवांजी पी.देसाई

(iiए) बर्बादी के ऐसे कार्य करता है, या कर रहा है जिससे मूल्य में भौतिक रूप से कमी आने की संभावना है, या उपयोगिता, या परिसर को काफी हद तक नुकसान पहुंचने की संभावना है, या

(iii) अन्यथा किसी भी व्यक्त या निहित शर्तों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया है, जिसके तहत वह ऐसे परिसर पर कब्जा करने के लिए अधिकृत है, या

(बी) कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी परिसर पर अनधिकृत कब्जे में हो, या

(सी) कि नामित किसी भी सरकारी परिसर की आवश्यकता किसी अन्य सरकारी प्रयोजनों के लिए है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिस (i) डाक द्वारा, या (ii) बाहरी दरवाजे या ऐसे परिसर के किसी अन्य विशिष्ट भाग पर इसकी एक प्रति चिपकाकर, या (iii) ऐसे अन्य तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है, तामील कराया जा सकता है, आदेश दें कि, उस व्यक्ति के साथ-साथ किसी भी अन्य व्यक्ति जो पूरे परिसर या उसके किसी हिस्से पर कब्जे में हो सकता है, नोटिस की तामील की तारीख से एक महीने के भीतर उन्हें खाली कर देगा।

(2) किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उपधारा (1) के तहत आदेश दिए जाने से पहले सक्षम प्राधिकारी आगे दिए गए तरीके से सभी संबंधित

व्यक्तियों को कारण बताने के लिए लिखित रूप में एक नोटिस जारी करेगा कि बेदखली का आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

नोटिस होगा,-

(ए) उस आधार को निर्दिष्ट करें जिस पर बेदखली का आदेश प्रस्तावित है; और

(बी) सभी संबंधित व्यक्तियों से, यानी उन सभी व्यक्तियों से, जो सरकारी परिसरों पर कब्जा में हैं या कर सकते हैं या इसमें रुचि का दावा कर सकते हैं, प्रस्तावित आदेश के खिलाफ, यदि कोई हो, ऐसी तारीख को या उससे पहले जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट है कारण बताने की आवश्यकता होगी।

यदि ऐसा व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी को नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के विस्तार के लिए आवेदन करता है तो सक्षम प्राधिकारी नोटिस में दावा की गई राशि के भुगतान और वसूली के लिए ऐसी शर्तों पर अनुमति दे सकता है, जैसा वह उचित समझे।

किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी लिखित बयान और नोटिस के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ मामले के रिकॉर्ड के साथ दायर किए जाएंगे और ऐसा व्यक्ति वकील, प्रतिनिधि या वकील के माध्यम से इस संबंध में कार्यवाही करने वाले अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का हकदार होगा।

इस उपधारा के तहत तामील किए जाने वाले नोटिस को बाहरी दरवाजे पर या परिसर के कुछ विशिष्ट हिस्से पर चिपकाकर, और ऐसे तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है, तामील किया जाएगा; और उसके बाद यह नोटिस सभी संबंधित व्यक्तियों को विधिवत दिया गया माना जाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को परिसर से बेदखल कर सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है और उस उद्देश्य के लिए आवश्यक बल का उपयोग कर सकता है।

(4) सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (3) के तहत जिस व्यक्ति से सरकारी परिसर का कब्जा लिया गया है, उसे चौदह स्पष्ट दिन का नोटिस देने के बाद और इस तरह के नोटिस को आधिकारिक राजपत्र में और कम से कम इलाके में एक प्रसार वाले समाचार पत्र में प्रकाशित करने के बाद, ऐसे परिसर में बची हुई किसी भी संपत्ति को हटा या हटवा सकता है या सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसका निपटान कर सकता है। ऐसा नोटिस उप-धारा (।) के तहत नोटिस की सेवा के लिए प्रदान किए गए तरीके से परोसा जाएगा।

(2) जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी परिसर पर अनधिकृत कब्ज़े में है, सक्षम प्राधिकारी, निर्धारित तरीके से और नुकसान के आकलन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, परिसर के उपयोग और कब्जे के कारण इस तरह के नुकसान का आकलन जैसा उचित समझे कर सकता है।, और (i) डाक द्वारा या (ii) बाहरी दरवाजे या ऐसे परिसर के किसी अन्य विशिष्ट भाग पर इसकी एक प्रति चिपकाकर, या (iii) ऐसे अन्य तरीके से, जो निर्धारित किया जा सकता है, नोटिस भेजकर उस व्यक्ति को नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर नुकसान का भुगतान करने का आदेश दें। यदि ऐसा व्यक्ति नोटिस में निर्दिष्ट समय के भीतर नुकसान का भुगतान करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो उससे भू-राजस्व के बकाया के रूप में नुकसान की वसूली की जा सकती है।

(सी) उप-धारा (2) के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को कारण बताने के लिए एक उचित अवधि के भीतर लिखित रूप में नोटिस जारी नहीं किया जाता है, जो ऐसे नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा कि ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, और जब तक सरकार बनाम मारवांजी पी.देसाई 655 उसकी आपत्तियों, यदि कोई हो, और उसके समर्थन में वह जो भी साक्ष्य पेश कर सकता है, उस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया जाता है।

धारा 6: किराया कर्मचारी के वेतन या पारिश्रमिक से कटौती करके वसूल किया जाएगा। - (1) धारा 4 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां कोई भी व्यक्ति जिसे सरकारी परिसर आवंटित किया गया है, -

(ए) राज्य सरकार का एक कर्मचारी, या

(बी) एक स्थानीय प्राधिकारी का एक कर्मचारी, जिसने उप-धारा (2) में दिए गए अनुसार एक समझौता निष्पादित किया है और ऐसे सरकारी परिसर के संबंध में देय किराया बकाया है, तो ऐसे परिसर के संबंध में देय किराए की राशि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में मांग करने पर वेतन या मजदूरी से काटी जाएगी।ऐसी मांग प्राप्त होने पर, सरकारी विभाग या कार्यालय का प्रमुख जिसके अधीन ऐसा व्यक्ति कार्यरत है, या, जैसा भी मामला हो, स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे व्यक्ति को देय वेतन या मजदूरी से मांग में निर्दिष्ट राशि काट लेगा। , और उपरोक्त देय राशि की संतुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी को कटौती की गई राशि का भुगतान करें।

(2) स्थानीय प्राधिकारी का कोई कर्मचारी, जिसे सरकारी परिसर आवंटित किया गया है, राज्य सरकार के पक्ष में एक समझौता निष्पादित कर सकता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि वह स्थानीय प्राधिकारी जिसके द्वारा या जिसके अधीन वह नियोजित है, समय-समय पर वेतन या मजदूरी से कटौती करने में सक्षम होगा। उसे देय, ऐसी राशि जो

समझौते में निर्दिष्ट है, और उसे आवंटित किसी भी सरकारी परिसर के संबंध में उसके द्वारा देय किसी भी राशि की संतुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी को कटौती की गई राशि का भुगतान करना होगा।

6 ए. सक्षम प्राधिकारियों की शक्ति. - एक सक्षम प्राधिकारी को, इस अधिनियम के तहत कोई भी जांच करने के प्रयोजन के लिए, वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट में निहित हैं, अर्थात् :-

(ए) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी जांच करना;

(बी) दस्तावेजों की खोज और उत्पादन की आवश्यकता;

(सी) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

धारा 7: अपील.- (1) धारा 4 या धारा 5 के तहत किसी भी सरकारी परिसर के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपील एक अपीलीय अधिकारी को की जाएगी, जो उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा जिसमें सरकारी परिसर स्थित हैं, या उस जिले में ऐसा कोई अन्य न्यायिक अधिकारी, जो कम से कम दस वर्ष का न्यायिक अधिकारी हो, जिसे जिला न्यायाधीश इस संबंध में नामित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत अपील की जाएगी -

(ए) धारा 4 के तहत एक आदेश से अपील के मामले में, धारा की उपधारा (1) के तहत आदेश से संबंधित नोटिस की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर; और

(बी) धारा 5 के तहत एक आदेश से अपील के मामले में, उस धारा की उपधारा (1) या (2) के तहत आदेश से संबंधित नोटिस की सेवा की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो :

बशर्ते कि अपीलीय अधिकारी तीस दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील की जाती है, अपीलीय अधिकारी उस आदेश के प्रवर्तन को उस अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर रोक सकता है जो वह उचित समझे।

(4) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील का निपटान अपीलीय अधिकारी द्वारा यथासंभव शीघ्रता से किया जाएगा।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ग्रेटर बॉम्बे को एक जिला माना जाएगा और सिटी सिविल कोर्ट, बॉम्बे के प्रधान न्यायाधीश को जिले का जिला न्यायाधीश माना जाएगा।

वैधानिक प्रावधानों का यह लंबा वर्णन मामले की प्रभावी सराहना के लिए अन्यथा अपरिहार्य है, खासकर प्रासंगिक तथ्यों में।

श्री ढोलकिया, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और हमेशा की तरह वाक्पटु हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धारा 7 को सही ढंग से पढ़ने पर कोई भी उच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है कि अधिनियम 1955 के अर्थ में सक्षम प्राधिकारी सरकार की एक सरकार बनाम मारवांजी पी.देसाई 657 विस्तारित शाखा या एक विभाग है और सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसे सरकार ही कहा जाना चाहिए और उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में स्पष्ट त्रुटि की है कि राज्य सरकार को सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम वर्तमान में तथ्यों को बहुत संक्षेप में दोहरा सकते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही 5 नवंबर, 1980 के आदेश द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हटा दी गई थी और इसी स्कोर पर श्री गणेश ने तर्क दिया कि सक्षम प्राधिकारी एक प्राणी है। क़ानून को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के उद्देश्य से नियुक्त किया गया है और तर्क दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि कार्यवाही सरकार द्वारा शुरू की गई है और उसके बाद मामला सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में तय किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सरकार का एक साधन है और वास्तव में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की तुलना सरकार के निर्णय से नहीं की जा सकती है और एक बार जब सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है तो अधिनियम की धारा 7 भीतर कोई अपील होने का प्रश्न नहीं है। श्री गणेश

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 की टिप्पणियों से प्रेरणा लेते हैं, जिसमें प्रावधान है: "कोई भी इच्छुक व्यक्ति, जिसने पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, कलेक्टर को लिखित आवेदन दे सकता है, आवश्यकता है कि मामले को कलेक्टर द्वारा निर्धारण के लिए न्यायालय को भेजा जाए।" और यूपी आवास एवं विकास परिषद एलआरएस द्वारा एवं बनाम ज्ञान देवी, [1995] 2 एससीसी पृष्ठ 326 में इस न्यायालय के निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी। हालाँकि, हम इस पर अपनी सहमति दर्ज करने में असमर्थ हैं। संविधान पीठ मूल रूप से स्थानीय प्राधिकरण के अधिकारों से चिंतित थी जिसकी कीमत पर भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और पीठ ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 50(2) की व्याख्या की। अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में मुआवजे की मात्रा के संबंध में कलेक्टर के आदेश को चुनौती स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के लिए प्रतिबंधित है जो पीड़ित है - कलेक्टर अधिग्रहित भूमि के लिए मौद्रिक मुआवजे का निर्धारण करता है और इस स्थिति में भूमि धारक इस प्रकार निर्धारित मात्रा से संतुष्ट नहीं होने पर, क़ानून की धारा 18 के संदर्भ में शिकायत को हवा देने का एक अवसर प्रदान करता है, अर्थात्, न्यायालय के समक्ष एक याचिका: यह अपील का अधिकार है लेकिन विधानमंडल ने भूमि धारक को विशेष रूप से अवसर प्रदान करने वाले ऐसे प्रावधान को क़ानून में शामिल करना उचित और समीचीन समझा। धारा में कलेक्टर के पास अपील करने का अधिकार पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर हम ऐसा कह सकते

हैं तो इसके लिए किसी न्यायिक मिसाल की आवश्यकता नहीं है। संविधान पीठ के फैसले में तथ्य यह है कि अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकला है कि जिस स्थानीय प्राधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसे अदालत के समक्ष उपस्थित होने और प्रतिस्पर्धा करने और यहां तक कि समर्थन में सबूत पेश करने का अधिकार है। इसके विवाद और अपील को प्राथमिकता देने का अधिकार है। संविधान पीठ के फैसले में तथ्य यह है कि अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से पढ़ने पर यह निष्कर्ष निकला है कि जिस स्थानीय प्राधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उसे अदालत के समक्ष उपस्थित होने और प्रतिस्पर्धा करने और यहां तक कि समर्थन में सबूत पेश करने का अधिकार है। इसके विवाद और संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कलेक्टर के समक्ष तय की गई मात्रा से व्यथित होने की स्थिति में न्यायालय द्वारा धारा 18 के संदर्भ में पारित आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, जिसे न्यायिक कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है। या अर्ध न्यायिक कार्यवाही भी, लेकिन न्यायालय के समक्ष धारा 18 के तहत याचिका दायर करने के साथ ही कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही का रूप ले लेती है और उससे जुड़ी सभी औपचारिकताओं का पालन करना होगा। धारा 18 में राज्य पर अपील के अधिकार को पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि राज्य ने स्वयं ही मात्रा तय कर दी है और क़ानून स्पष्ट रूप से भूमि धारक को प्रतिबंधात्मक अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार हम श्री

गणेश से सहमत नहीं हैं कि संविधान पीठ का निर्णय पूरी तरह से इस न्यायालय के समक्ष मुद्दे को कवर करता है। निर्णय पर निर्भरता पूरी तरह से गलत है और वास्तव में इसकी वर्तमान प्रासंगिक तथ्यों में कोई प्रासंगिकता नहीं है। नॉर्दर्न प्लास्टिक्स लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स एमएफजी. कंपनी लिमिटेड और अन्य, (1991] 4 एससीसी पृष्ठ 452) में इस न्यायालय के फैसले के संबंध में भी यही स्थिति है। इस न्यायालय की यह टिप्पणी कि अपील क़ानून का प्राणी है और इस प्रकार अपील के अधिकार का प्रयोग केवल क़ानून द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, इसे कानून की सही व्याख्या नहीं कहा जा सकता है और हम सम्मानपूर्वक इसके साथ अपनी सहमति दर्ज करते हैं। लेकिन जैसा कि ऊपर देखा गया है, नॉर्दर्न प्लास्टिक्स लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले की प्रासंगिक तथ्यों में कोई प्रासंगिकता नहीं है। श्री गणेश ने हालांकि कमजोर ढंग से तर्क दिया कि कार्यवाही को रद्द करने को अधिनियम की धारा 4 के अर्थ में एक आदेश नहीं कहा जा सकता है और इसके समर्थन में यह तर्क दिया गया था कि धारा 4 के तहत आदेश पारित करने के लिए पूर्व शर्त यह है कि सक्षम प्राधिकरण को धारा 4(1) में खंड (ए) या (बी) या (सी) में उल्लिखित परिस्थितियों या शर्तों से संतुष्ट होना चाहिए। संयोग से, धारा 4 के शुरुआती शब्द हैं "यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट है"। श्री गणेश ने तर्क दिया कि केवल उक्त संतुष्टि के अस्तित्व में पाए जाने के प्रभाव या परिणाम के रूप में, बेदखली का आदेश पारित किया जा सकता

है और यदि दूसरी ओर ऐसी कोई संतुष्टि नहीं होती है, तो धारा 4 के तहत कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता है और चूंकि वर्तमान में शर्तें पूरी नहीं होने पर, सक्षम प्राधिकारी ने बेदखली की कार्यवाही को रद्द कर दिया और इस प्रकार यह एक ऐसा आदेश नहीं हो सकता जो अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के तहत अपील योग्य हो। धारा 4(1), 4(2), 4(6) आदि की विशेष भाषा पर जोर दिया गया है, लेकिन श्री गणेश और उच्च न्यायालय द्वारा भी जो बात छूट गई है, वह है 1955 के अधिनियम की धारा 7 की स्पष्ट और श्रेणीबद्ध भाषा। "प्रत्येक आदेश" शब्दों का उपयोग यह दर्शाता है कि यह धारा 4 या धारा 5 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को व्यापक रूप से कवर करता है - श्री ढोलकिया ने यही तर्क दिया और हमें इसमें कुछ बल मिलता है। कार्यवाही को रद्द करने को संभवतः 'आदेश नहीं' कहा जा सकता है: सरकार बनाम मारवांजी पी.देसाई 659 सक्षम प्राधिकारी ने नोटिस जारी किया और पार्टियों को सुनवाई का अवसर देने पर, "कार्यवाही छोड़ दी गई" दर्ज करके कार्यवाही समाप्त कर दी – यदि यह समान नहीं दर्शाता है तत्काल पूछताछ होगी - फिर यह क्या है? हालाँकि, इसका कोई उत्तर नहीं है। यहां प्रतिवादी के खिलाफ अधिनियम की धारा 4 के तहत शुरू की गई कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी के निर्णय द्वारा निर्धारित की गई है और उच्च न्यायालय इस प्रकार स्पष्ट रूप से सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा कार्यवाही के निर्धारण के तथ्य की सराहना नहीं करने में त्रुटि में पड़ गया

है और यह है इस संबंध में श्री ढोलकिया ने तर्क दिया कि आदेश और कार्यवाही रद्द करने के बीच अंतर करने का प्रयास पूरी तरह से कृत्रिम और शायद अतार्किक है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी ने राज्य सरकार के तर्क को स्वीकार नहीं किया और वास्तव में बेदखली का निर्देश देने से इनकार कर दिया जो कि एक आदेश भी है उक्त धारा के तहत पारित किया गया। हम उस पर अपनी सहमति दर्ज करते हैं। हालाँकि, कार्यवाही को छोड़ने की कोई वैधानिक मंजूरी नहीं है।

हालांकि यह सच है, कि उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को सरकार का एक अंग या विंग होने के तथ्य पर भरोसा किया और इस तरह सक्षम प्राधिकारी को अपने आदेश के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी जा सकती - हालांकि, यह हमारे विचार में है यह क़ानून की पूरी तरह से गलत व्याख्या है और यदि इसे स्वीकार भी कर लिया जाता है, तो यह एक खतरनाक प्रस्ताव को जन्म देगा जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। हालाँकि, हम यह जोड़ने में जल्दबाजी करते हैं कि यदि क़ानून तब ऐसा चाहता था और उस स्थिति में, परिणाम की परवाह किए बिना, हम उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार पर अपनी सहमति दे सकते थे - दुर्भाग्य से, हालाँकि, क़ानून ऐसी व्याख्या की पुष्टि नहीं करता बल्कि इसे नकारता है। जैसा कि अपील के प्रावधान वाली धारा 7 में ऊपर देखा गया है, इस्तेमाल की गई भाषा की व्याख्या उसके उचित परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए न कि प्रतिबंधात्मक तरीके से। यदि उच्च

न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार किया जाना है तो उस स्थिति में क़ानून को अलविदा कहना होगा और इसे पूरी तरह से समाप्त कर देना होगा। शब्द " प्रत्येक ", धारा 7 में "आदेश" शब्द से ठीक पहले आता है, यह बेहद महत्वपूर्ण है ताकि सरकार के खिलाफ आदेश होने की स्थिति में अपील का अवसर प्रदान किया जा सके।

संयोग से, रिकॉर्ड दर्शाते हैं और जैसा कि तथ्य हमेशा होता है, कि कार्यवाही, वर्तमान में विचाराधीन क़ानून के तहत या समान प्रकृति के अन्य सभी क़ानूनों में, कलेक्टर या ऐसे किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि की मांग पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई है। विचाराधीन मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स दर्शाता है कि वास्तव में कलेक्टर की ओर से एक अनुरोध पत्र था और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान कलेक्टर का प्रतिनिधित्व प्रावधानों के संदर्भ में नोटिस के साथ एक अधिकारी द्वारा भी किया गया था। क़ानून और इस कारण से कार्यवाही को अर्ध न्यायिक कार्यवाही नहीं कहा जा सकता है।

गौरतलब है कि धारा 6 (ए) स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि अधिनियम के तहत जांच करने के उद्देश्य से, सक्षम प्राधिकारी के पास वही शक्तियां होंगी जो किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत सिविल कोर्ट में निहित होती हैं: जबकि यह सच है कि यह निहित गवाहों को बुलाने और किसी व्यक्ति की उपस्थिति को लागू

करने और शपथ पर उसकी जांच करने या दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुती की आवश्यकता तक सीमित है, लेकिन यह कार्यवाही की अर्ध न्यायिक प्रकृति को दूर नहीं करता है वस्तुतः यह ऐसे निष्कर्ष को विश्वसनीयता प्रदान करता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा गवाहों को बुलाना या उनकी उपस्थिति को लागू करना केवल न्यायालय के आदेश द्वारा ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं - यह विशिष्ट शक्ति है, जो सक्षम प्राधिकारी को प्रदान की जाती है ताकि सक्षम प्राधिकारी को इसके अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति मिल सके। प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने पर कानून: "कार्यवाही रद्द कर दी गई" को कार्यवाही को खारिज करने के आदेश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और इसके विपरीत श्री गणेश की कठोर अधीनता जैसा कि ऊपर देखा गया है, हमें डर है, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम या आयकर अधिनियम के प्रावधानों से लिया गया सादृश्य पूरी तरह से अनुचित और गलत है और इस प्रकार इस स्कोर पर भी कायम नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष क़ानून को अप्रभावी बना देगा, जिसकी किसी भी तरह से अनुमति नहीं दी जा सकती। इस कार्यवाही में अधिनियम की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है और इस प्रकार हम इसमें नहीं जा रहे हैं और क़ानून की व्याख्या और निर्माण के सुनहरे नियम के अनुसार, एक क़ानून को कानून का एक वैध टुकड़ा माना जाना चाहिए जब तक कि उचित फोरम द्वारा अमान्य घोषित न किया जाए। उस दिशा से संबंधित

कानून इतनी अच्छी तरह से स्थापित है कि हमें इसके बारे में विस्तार करने या खुद को रोकने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 3 की व्याख्या, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गई है को संभवतः अपनाया नहीं जा सकता और न ही क़ानून को उस तरीके और ढंग से पढ़ा जा सकता है जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया है। अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धारा 3 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति से यह संकेत मिलता है कि प्राधिकरण प्रशासनिक है और न तो न्यायिक और न ही अर्ध न्यायिक है, लेकिन इसे पूरी तरह से गलत नहीं माना जा सकता है। क़ानून पर पूरी तरह से विचार करना होगा और एक विशेष प्रावधान से एक शब्द चुनना और इस तरह वस्तुओं और कारणों के बयान के विपरीत इसका विश्लेषण करना न तो स्वीकार्य है और न ही उचित है। क़ानून के निर्माण और व्याख्या के कुछ निश्चित सिद्धांत हैं और सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के प्रशासनिक होने के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष न केवल क़ानून का उल्लंघन है, बल्कि निर्माण के सभी मानदंडों और सिद्धांतों के विपरीत है। किसी क़ानून को उस तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता जिस तरह से उच्च न्यायालय ने पढ़ा है। विधानमंडल के सच्चे इरादे को उसमें इस्तेमाल की गई भाषा का उचित ध्यान रखते हुए उसकी उचित भावना से एकत्र और सरकार बनाम मारवांजी पी.देसाई 661 समझा जाना चाहिए। वस्तुओं और कारणों का विवरण निस्संदेह निर्माण में सहायता और एक उपयोगी

मार्गदर्शिका है, लेकिन व्याख्याओं और इरादे को क़ानून की संपूर्णता से इकट्ठा करना होगा और जब किसी मंच पर अपील प्रदान करने वाले धाराओं की भाषा स्पष्ट और श्रेणीबद्ध हो तो इसकी व्याख्या में बाहरी सहायता की अनुमति है। विधायिका ने जानबूझकर "प्रत्येक आदेश" का उपयोग किया है और यदि प्रतिबंधात्मक अर्थ को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया है, तो किसी भी स्थिति में "प्रत्येक" शब्द पूरी तरह से अनावश्यक हो जाता है, लेकिन चूंकि विधानमंडल अतिरेक से बचता है और विशेष प्रावधान में उपयोग किए गए प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होना चाहिए और 'प्रत्येक' शब्द के किसी भी अर्थ का आरोपण स्वयं ही इस व्याख्या को अस्वीकार कर देगा जैसा कि उच्च न्यायालय के पक्ष में पाया गया है। 'प्रत्येक' शब्द को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है, जो न तो स्वीकार्य है और न ही जरूरी है।

इस मामले को देखते हुए अपील के तहत आदेश और निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह क़ानून के निर्माण और व्याख्या के सभी मानदंडों के विपरीत है।

इस प्रकार अपीलें स्वीकार की जाती हैं और अपीलों में दिए गए निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रारंभिक बिंदु पर खारिज कर दी गई थी और यहां पहले देखे गए परिणाम के कारण, हम निर्देश देते हैं कि अपीलों को इस आदेश के

संचार की तारीख से चार महीनों की अवधि के भीतर कानून की आवश्यकता के अनुसार संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा अत्यधिक शीघ्रता से सुना जाए।. कोई लागत नहीं।

एस.वी.के. अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ममता गुप्ता(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |